दिल्ली चलो **दिल्ली चलो**

मांगों के लिए 25 नवम्बर को दिल्ली की संसद का घेराव होगा

23 नवम्बर दिन सोमवार को भोपाल में इकठ्ठ होगे

दिल्ली की सरकार ने जो नई नीति बनाई है उससे गांन के गरीब मजदूरो एवं छोटे किसानों का जीना दूभर हो गया हैं सो दिन में महगाई कम करने की बजाय मंहगाई और बढ़ी हैं। सभी चीजें मंहगी हो गई हैं। प्रांत की सरकार भी उसमें शामिल हैं। विदेशी कर्जा आम आदमी पर बढता जा रहा है। और रोजगार नहीं दिया जा, रहा है। गांव के गरीबों को जमीन नही बांटी जा रही हैं। गांव के बढे लोगों के कब्जे में लाखों एकड़ जमीन है उनसे वह जमीन नहीं छीनी जा रही हैं। सीलिंग की जमीन नही बांटी जा रही हैं। लाखों भूमिहीनों के जुर्माने एवं कब्जे की जमीनों की फसलें चराई जा रही है। बर्षों से काबिज अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को राजस्व वन भूमि के पट्टे नहीं दिये जा रहे है। केबल घोषणाए की जा रही हैं। सिचाई के लिए बिजली लगाने के लिए आधिक पैसा लिया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी किसी भी गांव में लागू नहीं है। कंट्रोल से सस्ता अनाज खाने और जलाने का तेल नहीं मिल रहा है। नई नीति के कारण बेकारी बढ़ रही है। पढे लिखे नोजबानों को नौकरी नही मिल रही है। हर तरफ रिश्वत और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। गरीबों का शोषण हो रहा और अत्याचार बढ़ रहे हैं। सरकारी कारखाने बढ़े पूंजीपतियों को दिये जा रहें हैं।

वायदे पूरे करो

हमारी माँगे

1) बेजमीनों को जमीन दो।
2) कब्जे बालों भूमिहीनों को पट्टे दो ;
3) बेदखलियां बंद करो।
4) सीलिंग कानून पर अमल कर भूमिहीन गरीवों को जमीन बांटो वेनामी हस्तांतरण रद्द करो।
5) बढे बढे भूस्वामियों के अतिक्रमण हटाओ।
6) वनभूमि के कब्जे वाले व्यवस्थापन करो।
7) वनभूमि, गरीब भुमिहीनो खेती एवं पेड़ लगाने के लिए पट्टा दो
8) आदिवासी ग्रामों में स्कूल एवं ग्रामोद्योग खोलो।
9) बेरोजगारों को काम दो या बेकारी भत्ता दो।
10) गांव से गांव जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण करो।
11) जवाहर रोजगार योजना शक्ति से लागू करो।
12) भूमिहीन मजदूरों पर अप्याचार बद करो ।
13] न्यूनतम मजदूरी पर अमल करो।
14) छोटे किसानों को बिजली मुफ्त दो।
15] हनुमंत राव आयोग कीं रिपोर्ट लागू करो। भूलगम्मी भूमि सुधार लागू करो।

इन सभी मागो को लेकर भूमिहीन मजदूर, गरीब किसान, बेरोजगार नोजवान, महिलाए दिनांक 23 नवम्बर 92 दिन सोमवार को दोपहर 12 बजे तक भोपाल में लेडी अस्पताल के सामने पार्क में एकठ्ठ होंगे। अपने साथ 4 दिन का खाना ओढने का चादर भी साथ लावें। यह पर्चा खुद पढ़ें दूसरों को सुनायें और आस पास के गांव में भेजें।

हम है आपके साथी

कामरेड बालकृष्ण गुप्ता — अध्यक्ष

कामरेड हरीराम रोहितास — महासचिव

कामरेड हबीब — सचिव

मध्य प्रदेश खेत एवं वन मजदूर यूनियन, भोपाल, राज्य समिति

अन्य साथी प्रहलाद बैरागी, दोराहा, कामरेड हसमत अली भोपाल, का0 मदन जोशी, छोटेलाल दीवानगंज, कालूराम देहरी, [illegible] अम्बाड़ी, कामरेड अन्सूयियां मु0 सगीर मंसूरी रायसेन, बालमकुन्द दाहोद, गोमा जी सालीखेड़ा, मैरसिंह कंकड़िया आदि।

दिल्ली चलो   दिल्ली चलो

अंबेडकर जन्मशती पर संविधान की रक्षा के लिए, सामाजिक न्याय व साम्प्रदायिक़ता के विरोध में

१४ अप्रेल ६३ को दिल्ली की संसद पर प्रदर्शन

१२ अप्रेल दिन सोमवार को भोपाल में इकट्ठा होंगे

दिल्ली की सरकार ने जो नई नीति बनाई है उससे गांव के गरीब मजदूरों एवं छोटे किसानों का जीना दूभर हो गया है नये बजट से महंगाई कम करने की बजाय महंगाई और बढ़ी है। सभी चीजें महंगी हो गई हैं। प्रांत की सरकार भी उसमें शामिल हैं। विदेशी कर्जा आम आदमी पर बढ़ता जा रहा है। और रोजगार नहीं दिया जा रहा है। गांव के गरीबों को जमीन नहीं बांटी जा रही है। गांव के बढ़ लोगों के कब्जे में लाखों एकड़ जमीन है उनसे वह जमीन नहीं छीनी जा रही है। सीलिंग की जमीन नहीं बांटी जा रही है। लाखों भूमिहीनों के जुर्माने एवं कब्जे की जमीनों से बेदखल किया जा रहा है। वर्षों से काबिज अनुसूचित जाति एवं जनजाति के लोगों को राजस्व वन भूमि के पट्टे नहीं दिये जा रहे हैं। केवल घोषणायें की जा रही हैं। सिंचाई के लिए बिजली लगाने के लिए अधिक पैसा लिया जा रहा है। न्यूनतम मजदूरी किसी भी गांव में लागू नहीं है। कंट्रोल से सस्ता अनाज खाने और जलाने का तेल नहीं मिल रहा है। नई नीति के कारण बेकारी बढ़ रही है। पढ़े लिखे नौजवानों को नौकरी नहीं मिल रही है। हर तरफ रिश्वत और भ्रष्टाचार का बोलबाला है। गरीबों का शोषण हो रहा है और अत्याचार बढ़ रहे हैं। सरकारी कारखाने निजी पूंजीपतियों को दिये जा रहे हैं। मंडल, महाजन कमीशन पर कोई अमल नहीं हो रहा है। पिछड़ी जातियों पर अत्याचार बढ़ रहे हैं। इसलिए

वायदे पूरे करो

हमारी माँगें :-

- बेजमीनों को जमीन दो।
- बेदखलियां बन्द करो।
- सीलिंग कानून पर अमल कर भूमिहीन गरीबों को जमीन बांटो बेनामी हस्तांतरण रद्द करो।
- बड़े-बड़े भूस्वामियों के अतिक्रमण हटाओ।
- वनभूमि के कब्जे वालों का व्यवस्थापन करो।
- आदिवासी ग्रामों में स्कूल एवं ग्रामोद्योग खोलो।
- गांव से गांव जोड़ने के लिए सड़कों का निर्माण करो।
- भूमिहीन मजदूरों पर अत्याचार बन्द करो।
- छोटे किसानों को बिजली मुफ्त दो
- खेतिहार मजदूरों के लिए अलग से केन्द्रीय कानून बनाओ।
- ओला पीड़ित किसानों को उचित मुआवजा दो। साथ ह उन ग्रामों के ओला पीड़ित खेतिहर मजदूरों को प्रति परिवार 2 हजार रु सहायता दो, राहत कार्य चालू करो।
- कब्जे वाले भूमिहीनों को पट्टे दो।
- वनभूमि, गरीब भूमिहीनों खेती एवं पेड़ लगाने के लिए पट्टा दो।
- बेरोजगारों को काम दो या बेकारी भत्ता दो।
- जवाहर रोजगार योजना शक्ति से लागू करो।
- न्यूनतम मजदूरी पर अमल करो।
- हनुमंत राव आयोग की रिपोर्ट लागू करो। मूलगामी भूमि सुधार कानून पर अमल करो।
- धर्म को राजनीति से अलग करो। साम्प्रदायिकता फैलाने वालों के खिलाफ सख्त कानून बनाओ।

इन सभी मांगों को लेकर भूमिहीन मजदूर, गरीब किसान, बेरोजगार नौजवान, महिलायें दिनांक १२ अप्रेल ६३ दिन सोमवार को दोपहर १२ बजे तक भोपाल में लेडी अस्पताल के सामने पार्क में एकत्रित होंगे। अपने साथ 4 दिन का खाना ओढ़ने का चादर भी साथ लावें। यह पर्चा खुद पढ़ें दूसरों को सुनायें और आस पास के गांव में भेजें।

हम हैं आपके साथी

कामरेड बालकृष्ण गुप्ता
प्रांतीय अध्यक्ष

कामरेड हरीराम राहितास
प्रांतीय महासचिव

कामरेड हबीब
जिला सचिव

मध्यप्रदेश खेत एवं वन मजदूर यूनियन, भोपाल राज्य समिति

अन्य साथी प्रहलाद बैरागी, दोराहा, कामरेड हसमत अली भोपाल, का. मदन जोशी, छोटेलाल दीबानगंज, कालूराम देहरी, धन्नालाल अम्बाड़ी, का. अन्नू मियां, मु. सगीर मंसूरी रायसेन, बालमुकुन्द दाहोद, गोमाजी सालीखेड़ा, भैरसिंह कंकड़िया आदि।